		सदस्य होते है । यह समिति राज्य स्तर पर नीति संबंधी निर्देश देती है तथा पनधारा विकास परियोजना को समर्थन प्रदान करती है ।
	2. राज्य स्तरीय परियोजना संस्वीकृति एवं कार्यान्वयन समिति	राज्य के मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते है तथा कृषि, वानिकी, पशुपालन, बागवानी आदि के प्रभारी सचिव इसके सदस्य होते है । यह समिति पनधारा विकास परियोजना के लिए मंजूरी जारी करती है तथा उनके कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करती है ।
जिला स्तर	जिला स्तरीय परियोजना आयोजना एवं कार्यान्वयन समिति	जिला समाहर्ता इस समिति के अध्यक्ष होते है तथा जिले के मुख्य विकास अधिकारी और जिला स्तर के संबद्ध विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होते है । इस समिति का उत्तरदायित्व पनधारा विकास दलों द्वारा तैयार की गई पनधारा विकास परियोजनाओं की संवीक्षा करना तथा उन्हें राज्य स्तर की संस्वीकृति समिति के अनुमोदन के लिए सिफारिश करने का है । यह समिति परियोजना के निर्विघ्न क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए भी जिम्मेवार है ।
पनधार स्तर	1. पनधारा विकास दल	कृषि, वानिकी, पशुपालन, बागवानी, मृदा संरक्षण विभागों से लिए गए अधिकारियों का यह एक बहुआयामी दल है । यह बहुआयामी दल विभिन्न पनधारा विकास क्रियाकलापों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार है ।

धान का उत्पादन

1552. **श्री प्रमोद महाराज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धान का उत्पादन बढ़ाने और इसकी क्वालिटी में सुधार करने हेतु क्या प्रयत्न किए जा रहे है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 24 चावल उत्पादक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है । इस योजना के माध्यम से उच्च उत्पादक किस्मों के प्रमाणित बीजों, सूक्ष्म पोषकों खरपतवार नाशकों, पौध रक्षण रसायनों, पौध रक्षण उपकरणों, उन्नत कृषि औजारों आदि के उपयोग पर किसानों को सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें चावल उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय चावल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सतत तथा क्रमबद्ध प्रयास कर रहे है ।

Comparative profits between farm and milk product sectors

15S3. SHRI SOM PAL:
SHRI SARADA MOHANTY:
Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that producers' profits under crops in the farm sector are still superior to those of milk production on per hectare land basis;

(b) if so, whether Government have made any study on the comparative returns pattern for major crops and milk;

(c) if so, what are the details thereof: and

(d) what steps are being taken to improve the return from milk production ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) It is difficult to compare producers' profit under crops in the farm sector and those of milk production on per hectare land basis due to various multiple input-output factors responsible for their production.

(b) and (c) NDRI (1976-77 to 1978-79) have been conducting various studies to study Income and investment pattern in dairy and crop enterprises. It has been observed that the average cost for arable unit (of 2 acres) is Rs. 2539 and for dairy unit (3 milk cows and one acre of intensive farming) is Rs. 1438. The corresponding annual return from each of these programmes is Rs. 2184 and 1096 respectively.